करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **5**

- अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) 5
- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना 5
- अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी आरक्षण संबंधी स्थायी समिति 6
- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 6
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा योजना 7
- 'चंदैनी गोंदा- एक सांस्कृतिक यात्रा' (Chandaini Gonda-Ek Sanskritik Yatra) 7
- टूरिस्ट पुलिस (Tourist Police) 8
- सार्वजनिक ऋण में वृद्धि (Increase in Public Debt) 8
- औषधीय पौधों का संरक्षण व संवर्द्धन (Conservation and Promotion of Medicinal Plants) 9
- जीएसटी संग्रहण में वृद्धि (GST Collection in July) 9
- रायपुर नगर निगम 10
- महासमुंद जल परीक्षण प्रयोगशाला को NABL से मिली मान्यता 10

नोट :

- महासमुंद ज़िले में मिला चित्रित शैलाश्रय (Painted Rock Shelter Found in Mahasamund) 10
- जाति प्रमाण-पत्र 11
- एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रोजेक्ट 11
- छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय स्तर के दस पुरस्कार 12
- पाटजात्रा के साथ बस्तर दशहरा शुरू 12
- छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार : हरेली 13
- छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस 13
- सीतानदी टाइगर रिज़र्व 14
- पूना नार्कोम अभियान 14
- आईसीएमआर श्वसन रोग अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी 14
- प्रौढ़ साक्षरता हेतु एमओयू 15
- छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन 15
- उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल 16
- सतीश जायसवाल 16
- स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा 17
- इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम 17
- जगदलपुर में कैनोइंग-क्याकिंग की खेल सुविधा प्रारंभ 18

नोट :

- गम्हरिया गाँव बना प्लास्टिक और कचरा मुक्त 18
- 'सुगंधित कोंडानार अभियान' 19
- प्रमोद कुमार शुक्ला 19
- ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये ओलंपियाड 19
- मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद स्मारक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया 20
- 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' की दूसरी किस्त का भुगतान 20
- नव घोषित ज़िला मनेंद्रगढ़ का नाम अब 'मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर' 20
- शत-प्रतिशत टीकाकरण वाला प्रदेश का पहला ज़िला बना रायगढ़ 21
- गणित ऑलम्पियाड 21
- राज्य के 1242 गोठान हुए स्वावलंबी 22
- वन अधिकार दावों को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी 22
- ट्राईफेड के आउटलेट का शुभारंभ 23
- वनधन विकास केंद्रों को मिला सम्मान 23
- सूखा प्रभावित किसानों को वित्तीय मदद 23

नोट :

छत्तीसगढ़

अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)

चर्चा में क्यों ?

- 27 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य के चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- यह अनुपूरक बजट 2485 करोड़ रुपए का है।
- इस बजट में 'जल जीवन मिशन योजना' के लिये सर्वाधिक 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसी तरह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिये 208 करोड़ रुपए, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के लिये (न्याय योजना के तहत) 200 करोड़ रुपए तथा कर्ज़ का ब्याज चुकाने के लिये 105 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
- अनुपूरक बजट में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के लिये 4 करोड़ रुपए, साजा में 50 बिस्तर के एमसीएच (मातृ-शिशु) की स्थापना के लिये 1.60 करोड़ रुपए तथा रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना के लिये 1.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बजट में अन्य प्रावधान हैं-
  - संचार क्रांति योजना - 100 करोड़ रुपए
  - राष्ट्रीय आजीविका मिशन - 121.90 करोड़ रुपए
  - मजरा टोला विद्युतीकरण योजना - 58 करोड़ रुपए
  - मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लीनिक योजना - 7 करोड़ रुपए

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

- 28 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट में ` 200 करोड़ के प्रावधान के साथ एक नई योजना 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' (Rajiv Gandhi Grameen Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Yojna) की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अनुपूरक बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की।
- इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मज़दूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- इस योजना से मुख्य रूप से राज्य के मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर किया जाएगा।
- सरकार की इस योजना से राज्य के लगभग 10 लाख से ज़्यादा मज़दूरों को फायदा मिलेगा।
- ध्यातव्य है कि अभी तक केंद्र की मोदी सरकार छोटी और मध्यम जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिये महत्त्वपूर्ण होगी।

नोट :

अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी आरक्षण संबंधी स्थायी समिति

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये स्थायी आरक्षण समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत इस समिति का गठन किया गया है।
- राज्य के आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय इस स्थायी समिति में पाँच विधायक और सामान्य प्रशासन विभाग व आदिम जाति विकास विभाग के सचिव शामिल हैं।
- समिति का मुख्य कार्य अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना है।
- इसके अलावा यह समिति अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सुझाव भी देगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थायी समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 सितंबर, 2019 को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्थगित करते हुए क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (Chandulal Chandrakar Memorial Medical College Durg (Acquisition) Bill, 2021) ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
  - राज्य सरकार ने जनहित में इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यह प्रकरण भविष्य के दृष्टांत नहीं होगा, केवल वन टाइम परमिशन दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के निवासियों तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 फरवरी, 2021 को आयोजित कार्यक्रम में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर के राज्य शासन द्वारा अधिग्रहण की घोषणा की थी।
- मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण भू-अर्जन के नियमों के तहत किया जाएगा। भू-अर्जन के प्रावधानों के अंतर्गत ही संपत्ति का आकलन भी किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन के चार गुना भुगतान के स्थान पर मंत्रिमंडल द्वारा दो गुना तक मूल्यांकन करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार निर्धारित राशि के अतिरिक्त न तो किसी राशि का भुगतान किया जाएगा और न अन्य कोई दायित्व होगा। इससे सरकार को कम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज में अभी भी कई छात्र (भावी डॉक्टर) अध्ययनरत् हैं। इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से हर वर्ष 150 नए डॉक्टर मिलेंगे।

नोट :

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा योजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential Schools) में ऑनलाइन शिक्षण हेतु विभाग द्वारा योजना तैयार की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य इन विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षक द्वारा सीबीएसई व सीजी बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाई कराना, विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़े रखना, नियमित टेस्ट का मूल्यांकन, विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और मार्गदर्शन, विद्यार्थियों के पालकों से संपर्क और विद्यार्थियों की परेशानी ज्ञात कर उनका निराकरण करना है।
- योजना में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये स्कूल स्तर पर ऑनलाइन अध्यापन का सेटअप तैयार कर विद्यार्थियों को गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है।
- ऑनलाइन शिक्षण का लाभ विद्यार्थियों को किस प्रकार मिल रहा है, इसके लिये विभागीय शिक्षकों, छात्रावास अधीक्षकों और मंडल संयोजकों के माध्यम से मैदानी स्तर पर मॉनिटरिंग का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है।
- योजना के तहत व्यवस्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को नोडल विद्यालय बनाया जाएगा और यहीं से ज़िले के अन्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जहाँ ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा नहीं हो, को भी ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।
- प्रत्येक ज़िले में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को नोडल स्कूल के रूप में चिह्नांकित किया जाएगा, जहाँ शिक्षक और ऑनलाइन शिक्षण हेतु संसाधन उपलब्ध होंगे। नोडल विद्यालय में किसी भी कक्षा, विषय में अध्यापन के लिये बच्चों का समूह 120 से अधिक नहीं होगा।
- स्थायी शिक्षकों और अन्य शालाओं से शिक्षक संलग्न कर टीम बनाई जाएगी। विषयवार प्रत्येक विषय के लिये एक कोरग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें उस विषय के न्यूनतम तीन शिक्षक होंगे।
- ऑनलाइन शिक्षक की आवश्यक व्यवस्था और मॉनिटरिंग सहायक आयुक्त, आदिवासी द्वारा और राज्य स्तर पर समीक्षा आयुक्त द्वारा की जाएगी। ग्राम स्तर से विभागाध्यक्ष स्तर तक मॉनिटरिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

'चंदैनी गोंदा- एक सांस्कृतिक यात्रा' (Chandaini Gonda-Ek Sanskritik Yatra)

चर्चा में क्यों ?

- 29 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉ. सुरेश देशमुख द्वारा लिखित 'चंदैनी गोंदा- एक सांस्कृतिक यात्रा' पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में वस्तुत: नई पीढ़ी को दाऊ रामचंद्र देशमुख के व्यक्तित्व और कृतित्व से समग्र रूप से परिचित कराने का प्रयास किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि 'चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा' स्मारिका का प्रकाशन 7 दिसंबर, 1976 को चंदैनी गोंदा के 25वें प्रदर्शन के अवसर पर हुआ था। इसके संपादक धमतरी के साहित्यकारद्वय सर्वश्री नारायण लाल परमार और त्रिभुवन पांडे थे।
- इस स्मारिका के प्रकाशन के 45 वर्षों के उपरांत इसके द्वितीय संस्करण को संशोधित और परिवर्धित रूप में प्रकाशित किया गया है।
- इस संस्करण में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा सृजित देहाती कला विकास मंडल (Dehati Kala Vikas Mandal) से लेकर चंदैनी गोंदा की निर्माण प्रक्रिया और उसके विसर्जन तथा कारी की सर्जना तक की सांस्कृतिक यात्रा को 488 पृष्ठों के इस पुस्तक में समाहित किया गया है।

नोट :

- डॉ. देशमुख ने अपने इस शोधपूर्ण ग्रंथ में दाऊ जी और उनकी कृतियों से जुड़े छोटे-बड़े सभी कलाकारों और साहित्यकारों का वर्णन कर उनके अवदानों को भी रेखांकित किया है।
- यह पुस्तक छत्तीसगढ़ में लोककला, संगीत और लोक संस्कृति को जानने तथा समझने का प्रयास करने वालों के लिये एक अनुपम उपहार के रूप में है। यह न केवल पठनीय है, अपितु संग्रहणीय भी है, जिससे भविष्य में लोककला के शोधार्थियों के लिये यह संदर्भ ग्रंथ का काम करेगा।

टूरिस्ट पुलिस (Tourist Police)

चर्चा में क्यों ?

- 31 जुलाई, 2021 को पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के घटारानी-जतमई से एक पर्यटक पुलिस स्थापित की गई।

प्रमुख बिंदु

- ज़िले के ज़्यादातर इलाके पर्यटन के लिये मशहूर हैं, लेकिन कई बार कुछ अप्रिय घटनाएँ घट जाती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पर्यटक पुलिस शुरू करने की घोषणा 30 जुलाई को की गई थी।
- इस पर्यटक पुलिस को अभी शुरुआत में ज़िले के चार स्थानों- घटारानी, जतमई, राजिव लोचन मंदिर और चिंगारापारा झरना में लॉन्च किया जाएगा।
- गरियाबंद ज़िला राजधानी रायपुर से 90 किमी. दूर स्थित है। उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व, सिकासार बाँध और भूतेश्वरनाथ, घटारानी, जतमई और राजीव लोचन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

सार्वजनिक ऋण में वृद्धि (Increase in Public Debt)

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बताया कि राज्य का कुल सार्वजनिक ऋण 2019-20 में 20.85 प्रतिशत बढ़कर 63,164.72 करोड़ रुपए हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 के लिये छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त और विनियोग लेखा को सदन में पेश करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को भी पेश किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ का कुल सार्वजनिक ऋण 2018-19 के 52,254.22 करोड़ रुपए से 20.85 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में 63,164.72 करोड़ रुपए हो गया है।
- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 17,969.55 करोड़ रुपए रहा, जो जीएसडीपी का 5.46 प्रतिशत है और जीएसडीपी के 2.99 प्रतिशत के एमटीएफपी (मनी फॉलो द पर्सन इनिशिएटिव) लक्ष्य से अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.07 प्रतिशत के एफआरएमबी (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) लक्ष्य के भीतर था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 का सकल बज़ट 1,06,913.44 करोड़ रुपए था। इसके खिलाफ सकल व्यय 92,261.34 करोड़ रुपए था।
- कर राजस्व 42,323.69 करोड़ रुपए रहा और राज्य का अपना राजस्व वर्ष 2018-19 के 21,427.26 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,117.85 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राज्य को केंद्र से 13,611.24 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है।
- राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 8,566,39 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2018-19 की तुलना में 337.06 करोड़ रुपए कम है। 2019-20 के दौरान 9,608.61 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.92 प्रतिशत है।

नोट :

- राज्य सरकार पर 78,712.46 करोड़ रुपए की बजटीय देनदारियों के अलावा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये 694.26 करोड़ रुपए की देनदारी है।

औषधीय पौधों का संरक्षण व संवर्द्धन (Conservation and Promotion of Medicinal Plants)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबैट डेजर्टीफिकेशन (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) द्वारा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उक्त संस्था UNCCD द्वारा इसके तहत राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है।
- यूएनसीसीडी ने मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विषय में चलाए जा रहे जागरुकता अभियान की और निर्मल अवस्थी की होम हर्बल गार्डन योजना के तहत औषधीय पौधों का ज्ञान तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित चिकित्सा पद्धति के पुनरुत्थान के लिये किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
- यूएनसीसीडी सचिवालय के रजेब बुलहारौत ने इसकी सरहाना करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर सम्मानित किया है।
- गौरतलब है कि पारंपरिक वैद्य संघ द्वारा प्रतिवर्ष औषधीय पौधों का नि:शुल्क वितरण कर छत्तीसगढ़ राज्य की लोक स्वास्थ्य परंपरा, संवर्द्धन अभियान एवं 'घर-अंगना, जड़ी-बूटी बगिया योजना' के तहत जन-जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
- प्रदेश के पारंपरिक वैद्यों के द्वारा मौसमी बीमारियों के अलावा असाध्य रोगों में जीवनदायिनी वनौषधियों, जिसमें ब्राह्मी अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कालमेघ, गिलोय, अडूसा, चिरायता, पत्थर चूर, मंडूपपर्णी, भुईआंवला, भृंगराज, हड़जोड़ आदि बहुउपयोगी वनौषधियों का वितरण किया जाता है।

जीएसटी संग्रहण में वृद्धि (GST Collection in July)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी केंद्र सरकार के आँकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के आँकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2,432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि में 33% से अधिक है। जीएसटी संग्रहण में हुई यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32% वृद्धि से अधिक है।
- छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल व आंध्र प्रदेश के जीएसटी संग्रहण की तुलना में अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड संकट की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चलती रहीं, जिसके कारण यह वृद्धि हुई है।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनोपज संग्रहण, गोधन न्याय योजना, वैल्यू एडिशन तथा आजीविका गतिविधियाँ, मनरेगा जैसे कदमों ने राज्य में आर्थिक गतिशीलता बनाए रखी।
- कोविड-19 के दौरान शुरू हुई 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से राज्य के 19 लाख किसानों को लाभ मिला, जबकि इस वर्ष 22 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।

नोट :

- वनोपज संग्रहण के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। वनोपजों के वैल्यू एडिशन और गोठानों में चलने वाली आजीविका गतिविधियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर निर्मित हुए हैं।
- इसके अलावा महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोज़गार मुहैया कराए गए। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही गोबर खरीदी, जैविक खाद के निर्माण और बिक्री से भी बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक तथा स्व-सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

रायपुर नगर निगम

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में प्रदेश के 13 नगर निगमों में रायपुर नगर निगम बिजली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान करने में प्रदेश भर में प्रथम रहा।

प्रमुख बिंदु

- निगम ने 1 जून से 31 जुलाई तक दर्ज़ शिकायतों के निराकरण करने के मामले में लंबी छलांग लगाते हुए खुद को 'D' से 'A' ग्रेड में पदोन्नत किया है।
- वार्डवासियों की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिये निगम मुख्यालय में निदान-1100 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें लोग अपनी समस्याओं को बताकर उनका समाधान प्राप्त करते हैं।
- निगम ने 78.25 फीसद शिकायतों का त्वरित निवारण, 19.47 फीसद शिकायतों का थोड़ा विलंब से निवारण किया जबकि तीन फीसद मामले लंबित रहे।

महासमुंद जल परीक्षण प्रयोगशाला को NABL से मिली मान्यता

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले में संचालित जल परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) ने मान्यता प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- NABL द्वारा मान्यता मिलने के बाद अब ज़िले के आम नागरिक जल परीक्षण करा सकते हैं, जिससे जल परीक्षण परिणाम में परिशुद्धता मिलेगी।
- गौरतलब है कि यह छत्तीसगढ़ की 10वीं NABL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशाला है।
- उल्लेखनीय है कि NABL, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका पंजीकरण 'संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1980' के तहत किया गया है।
- भारत सरकार ने NABL को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यापन निकाय के रूप में अधिकृत किया है।

महासमुंद ज़िले में मिला चित्रित शैलाश्रय (Painted Rock Shelter Found in Mahasamund)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िला की बागबाहरा तहसील के अंतर्गत ग्राम मोहदी के निकट महादेव पठार में एक चित्रित शैलाश्रय की खोज की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस शैलाश्रय की खोज संस्कृति विभाग के उप-संचालक डॉ. पी.सी. पारस के नेतृत्व में पर्यवेक्षक प्रभात कुमार एवं उत्खनन सहायक प्रवीन तिर्की द्वारा की गई है।
- इस शैलाश्रय में पुरातत्त्वीय महत्त्व के शैलचित्र मिले हैं। इन शैलचित्रों में नृत्य करते मानव समूह, वानर, सूर्य और चंद्रमा सहित ज्यामितीय आकृतियाँ लाल गेरुवे रंग से निर्मित हैं।
- यह महासमुंद ज़िले के अंतर्गत अब तक ज्ञात पहला चित्रित शैलाश्रय है। यहाँ उपलब्ध्य शैलचित्रों के आधार पर इस क्षेत्र में मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्राचीनता मध्यपाषाण काल तक संभावित है।
- उल्लेखनीय है कि महासमुंद ज़िले में सिरपुर और खल्लारी जैसे महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल पहले से ही विद्यमान हैं। सिरपुर को प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है।
- ज़िले के बरतियाभाठा से महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में मोहदी के निकट खोजा गया यह चित्रित शैलाश्रय स्थल महासमुंद ज़िले के इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन पुरास्थल माना जा सकता है।

जाति प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र) जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी ज़िलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिये गए हैं।
- राज्य शासन के आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्रामसभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- इसी तरह से अब नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर दिया गया है। इसके तहत नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- राज्य शासन के इस आदेश के बाद अब राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र) प्राप्त करना आसान हो गया है।

एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

- 5 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ में चल रहे एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (Integrated Road Accident Database-iRAD) परियोजना के कार्य प्रगति की केंद्रीय ई-परिवहन व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के उप-महानिदेशक ने सराहना करते हुए इस मॉडल का अन्य राज्यों को अनुसरण करने की सलाह दी है।

प्रमुख बिंदु

- देशभर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने तथा दुर्घटनाओं में नियंत्रण के लिये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) तथा IIT मद्रास के सहयोग से iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) मोबाइल ऐप और वेब एप्लिेशन तैयार किया है।

नोट :

- मई 2021 के अंतिम सप्ताह में इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई थी। राज्य टीम ने समय से पहले परियोजना को लागू कर अन्य राज्यों के लिये मिसाल कायम की है।
- सड़क दुर्घटना सड़क की बनावट, ट्रॉफिक कॉमिंग सहित अन्य सड़क सुरक्षा उपायों के न होने, मौसमी कारणों से या कोई अन्य कारणों से हुई हो, इसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से सीधे ज़िला/राज्य मुख्यालय सहित केंद्रीय परिवहन मुख्यालय तथा विश्लेषण/समीक्षा के लिये आईआईटी, मद्रास में पहुँच जाती है।
- दुर्घटना के कारणों की सही जानकारी होने से संबंधित विभागों के अधिकारीगण उस दुर्घटनाजन्य सड़क खंडों में आवश्यक सुधारात्मक उपायों हेतु पहल करेंगे।
- iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) के समुचित उपयोग से संबंधित विभागों को सही जानकारी मिल सकेगी। संबंधित विभागों की प्रचलित सेवाओं को एकीकृत/इंटरफेस किये जाने से वाहन का नंबर लिखते ही वाहन संबंधित पूरी जानकारी एप्लिकेशन उपयोगकर्त्ता को मिल जाएगी।
- इस पर अपलोड किये गए डाटा संबंधित विभागों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की भावी कार्य योजनाओं के लिये अत्यंत उपयोगी होंगे। प्रदेश के विभिन्न मार्गों में दुर्घटनाओं के सही कारण मालूम होने से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाने से दुर्घटनाओं में कमी संभावित है।

छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय स्तर के दस पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 6 अगस्त, 2021 को भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में दस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किये।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) द्वारा तीन श्रेणियों- न्यूनतम समर्थन मूल्य, वन धन तथा विक्रय एवं विपणन के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- प्रदेश को छह श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में निर्मित महुआ सेनिटाइजर और ईमली चस्का को नव उत्पाद एवं नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है।
- वन धन पुरस्कार 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ को लघु वनोपजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सर्वाधिक नए वनोपजों (52) को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल करने, भारत शासन की राशि से सर्वाधिक मूल्य (180.51 करोड़ रुपए) का लघु वनोपज खरीदने, केंद्र एवं राज्य शासन की राशि से सर्वाधिक मूल्य (1173 करोड़ रुपए) के लघु वनोपजों की खरीदी तथा वर्ष 2020-21 तक उपलब्ध कराई गई राशि (127.09 करोड़ रुपए) की अधिकतम उपयोगिता के लिये प्रथम पुरस्कार मिला है।
- इसी श्रेणी में सर्वाधिक सर्वेक्षण पूर्ण करने तथा वन धन विकास केंद्र क्लस्टरों के लिये सर्वाधिक प्रशिक्षण हेतु भी राज्य को तीसरा पुरस्कार मिला है।
- वन धन योजना के तहत मूल्य संवर्द्धन के लिये अधिकतम उत्पादों (121) के निर्माण तथा मूल्य संवर्धन कर उत्पादों की अधिकतम बिक्री (4.24 करोड़ रुपए) के लिये भी राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

पाटजात्रा के साथ बस्तर दशहरा शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 08 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध 75 दिनी बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ पाटजात्रा पूजा विधान के साथ हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बस्तर में हर वर्ष की तरह इस साल भी दशहरे का शुभारंभ हरेली अमावस्या को पाटजात्रा की प्रथम रस्म से शुरू हुआ।
- पाटजात्रा बस्तर दशहरा की प्रथम महत्त्वपूर्ण रस्म है, जिसमें दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष माचकोट के जंगल से लाई गई साल वृक्ष की लकड़ी (ठुरलू खोटला) की पारंपरिक रूप से पूजा-अर्चना की जाती है।
- बस्तर दशहरा निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में ठुरलू खोटला एवं टीका पाटा कहते हैं।
- बस्तर दशहरा की परंपरा के अनुसार, पाटजात्रा के लिये होने वाली पूजा में बस्तर महाराज की ओर से माझी-मुखिया पूजन सामग्री लेकर सिरहासार पहुँचते हैं और पाटजात्रा एवं अन्य पूजा विधान संपन्न कराते हैं।
- ध्यातव्य है कि बस्तर दशहरा की शुरुआत 1408 ई. में राजा पुरुषोत्तम देव ने शुरू की थी। उन्होंने जगन्नाथपुरी से वरदानस्वरूप मिले सोलह चक्कों के रथ का विभाजन करते हुए रथ के चार चक्कों को भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया था और शेष 12 पहियों का विशाल काष्ठ रथ माँ दंतेश्वरी को अर्पित कर दिया। तब से दशहरा में दंतेश्वरी के साथ राजा स्वयं भी रथारूढ़ होने लगे।

छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार : हरेली

चर्चा में क्यों ?

- 08 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम त्यौहार 'हरेली' हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष सावन माह में हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
- यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये विशेष महत्त्व रखता है। धान की बुआई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि एवं लौह औज़ारों की पूजा की जाती है।
- हरेली पर्व में किसान बैलों और हल सहित विभिन्न औज़ारों की विशेष पूजा करने के बाद खेती-किसानी का काम शुरु करते हैं।
- हरेली त्यौहार के दिन घरों में इस त्यौहार का विशेष व्यंजन 'चीला' बनाया जाता है। इसे औज़ारों में चढ़ाकर इसकी पूजा की है, तत्पश्चात् इसे घर के सदस्यों को प्रसादस्वरूप दिया जाता है।
- हरेली के दिन पुरुषों के द्वारा गेड़ी (बाँस से निर्मित) बनाकर उस पर चढ़ा जाता है। कहीं-कहीं गेड़ी दौड़ का आयोजन भी किया जाता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) द्वारा तैयार की गई जनजातीय एटलस का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- जनजातीय एटलस तैयार करने के मामले में ओडिशा और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ देशभर में तीसरा राज्य बन गया है।
- इस जनजातीय एटलस में राज्य की जनजातियों की संस्कृति, रीति-रिवाज, बोलियों की जानकारी, जनजातीय आर्ट एवं क्रॉफ्ट, तीज-त्यौहार, नृत्य, जनजातीय पर्यटन, राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ-साथ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में जानकारी का समावेश किया गया है।
- साथ ही इस एटलस में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय आश्रम शालाएँ/छात्रावास, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास विद्यालय जैसे आधारभूत शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी, राज्य में प्रशासनिक इकाइयाँ, समुदायवार जनजातीय जनसंख्या, लिंगानुपात, शैक्षणिक स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी का भी समावेश है।

नोट :

- इस एटलस में राज्य की 42 जनजातियों के संबंध में संक्षिप्त ज़िलेवार पर्यावास रूपरेखा इंसेट मैप के माध्यम से किया गया है।
- पर्यावास रूपरेखा के साथ-साथ ज़िलेवार प्रमुखता से निवासरत, जनजाति, वनक्षेत्र एवं विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसे चिप्स द्वारा तैयार किया गया है।
- एटलस में जनगणना 2011 में संस्थान द्वारा किये गए विशेष पिछड़ी जनजातियों के आधारभूत सर्वेक्षण एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सूचनाओं को भी शामिल किया गया है।

सीतानदी टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गरियाबंद ज़िले के सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्रों में बसे पाँच गाँवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सौंपा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में गरियाबंद ज़िले के इन पाँच गाँवों के वन अधिकार समितियों को सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार सौंपा है।
- अब इन पाँच गाँवों को 5553.26 हेक्टेयर (लगभग 14,000 एकड़) के जंगल पर प्रबंधन का अधिकार मिल गया है।
- सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्रों में बसे इन गाँवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य करने के बाद छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ यह अधिकार टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में भी दिया गया है।
- राज्य में यह पहला मौका है, जब टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया गया है। पिछले साल सीतानदी के बफर क्षेत्र में ग्राम करका को यह अधिकार दिया गया था।
- सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्रों में बसे जिन पाँच गाँवों को यह अधिकार दिये गए हैं, इनमें ग्राम मासुलखोई (975.58 हेक्टेयर), ग्राम करही (984.92 हेक्टेयर), ग्राम जोरातराई (551.42 हेक्टेयर), ग्राम बरोली (1389.61 हेक्टेयर) और ग्राम बहिगाँव (1651.72 हेक्टेयर) शामिल हैं।

पूना नार्कोम अभियान

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सुकमा ज़िला पुलिस द्वारा 'पूना नार्कोम अभियान' की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के तहत ज़िला मुख्यालय सहित ज़िले के विभिन्न जगहों में ग्रामीण अंचलों के आदिवासी ग्रामीणों के लिये ज़िला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया।
- इसके साथ ही ग्रामीणों को दैनिक उपयोगी सामग्रियों का वितरण भी किया गया।
- इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के साथ शासन की नीतियों के प्रति जागरुकता लाने की दिशा में काम किया जाएगा।
- पूना नार्कोम अभियान के तहत सुकमा पुलिस द्वारा रोज़गार के क्षेत्र में युवाओं को जागरुक किया जाएगा एवं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।

आईसीएमआर श्वसन रोग अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में साँस की गंभीर बीमारियों पर शोध के लिये एक केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- एम्स रायपुर में स्थापित होने वाला यह केंद्र देश में स्थापित किये जा रहे 20 केंद्रों में से एक होगा। इन केंद्रों को पल्मोनरी फाइब्रोसिस के आईसीएमआर नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है।
- यह श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले रोगों के संबंध में विस्तृत आँकड़े एकत्रित कर चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने में मदद करेगा।
- केंद्र के प्रधान अन्वेषक नियुक्त किये गए डॉ. अजय कुमार बेहरा ने बताया कि यह पाँच साल का प्रोजेक्ट है।
- रायपुर एम्स का पल्मोनरी विभाग रोजाना 250 मरीजों की रिपोर्ट करता है। यह केंद्र कोविड-19 के बाद के रोगियों का डेटा एकत्र करने और उनके उपचार का विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा।

प्रौढ़ साक्षरता हेतु एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रोटरी इंडिया लिट्रेसी मिशन एवं एससीईआरटी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में सहयोग हेतु निःशुल्क एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के तहत रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिये आगामी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन एवं स्टूडेंट वालंटियर्स को तैयार करने में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का सहयोग करेगा।
- प्रौढ़ शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिये स्थानीय रोटरी क्लब का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये सहायक गतिविधियों (ट्रेनिंग मॉड्यूल, सर्टिफिकेशन) एवं नेशन बिल्डर अवॉर्ड्स से पुरस्कृत करेगा।
- इसके साथ-साथ ई-लर्निंग सामग्रियों का निर्माण, वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन द्वारा सहयोग कार्यक्रम चलाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के वनांचल में उगाई जाने वाली कोदो-कुटकी और रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिये मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन से वनांचल में लोगों के पोषण स्तर पर वृद्धि होगी। वहीं इन फसलों के वैल्यु एडिशन से रोज़गार भी मिलेगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
- मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर कोदो-कुटकी के लिये जहाँ समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, वहीं 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' में इन फसलों को शामिल कर इनके लिये इनपुट सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है।
- लघु धान्य फसलों में पाए जाने वाले भरपूर पोषक तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए उत्तर बस्तर (कांकेर) ज़िले में ज़िला प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ज़िले के किसानों को मिलेट मिशन के तहत उन्नत खेती के लिये जानकारी दी जा रही है।
- कोदो-कुटकी के उत्पादन और संग्रहण के लिये किसान विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें 300 परिवार जुड़े हैं।
- लघु धान्य फसलों के वैल्यु एडिशन के लिये कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर और दुर्गुकोंदल विकासखंड के ग्राम गोटुलमुंडा में प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है। इन दोनों इकाईयों में एक-एक महिला समूहों द्वारा प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है।

नोट :

- संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य में लगी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 850 से अधिक मानव दिवस का रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। ज़िला प्रशासन की पहल पर लघु धान्य फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों और महिला समूहों को इस प्रसंस्करण केंद्र से जोड़ा गया है।
- इस केंद्र में तैयार किये गए उत्पाद आंगनबाड़ियों के माध्यम से कुपोषित, रक्ताल्पता से ग्रसित व गर्भवती माताओं तथा कुपोषित बच्चों को कोदो चावल खिचड़ी के रूप में एवं रागी को हलवा के रूप में प्रदान किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3 हज़ार रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो-कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9 हज़ार रुपए और धान के बदले कोदो-कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया है।

उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल

चर्चा में क्यों ?

- 12 अगस्त, 2021 को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के तीन अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष-2021 के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक इंदु शर्मा को अलग-अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा।
- उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा ने मार्च 2020 में, उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव ने जून 2019 में तथा सहायक उपनिरीक्षक इंदु शर्मा ने अक्तूबर 2020 में हुए बलात्कार की जांच में उच्च पेशेवर मानक को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल प्रदान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना हेतु इन पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी।

सतीश जायसवाल

चर्चा में क्यों ?

- 14 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में सुप्रसिद्ध लेखक सतीश जायसवाल को 21वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह का आयोजन गांधीवादी ग्रामसेवक स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोक जागरण की मासिक पत्रिका 'वसुंधरा' के द्वारा किया गया।
- संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की।
- समारोह में 'लोक जागरण' की मासिक पत्रिका 'वसुंधरा' के 58वें तथा कला, साहित्य, संस्कृति की मासिक पत्रिका 'बहुमत' के 109वें अंक का लोकार्पण भी किया गया। वसुंधरा का यह अंक छत्तीसगढ़ के 11 कहानीकारों की प्रतिनिधि कहानियों पर केंद्रित है।

नोट :

- गौरतलब है कि वर्ष 2001 से निरंतर जारी वसुंधरा सम्मान अब तक सर्वश्री रमेश नैयर, कुमार साहू, श्यामलाल चतुर्वेदी, बसंत कुमार तिवारी, बबन प्रसाद मिश्र, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, शरद कोठारी, गिरिजा शंकर, हिमांशु द्विवेदी, विनोद शंकर शुक्ल, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर, गिरीश पंकज, सुशील त्रिवेदी, बी.के.एस.रे, प्रकाश दुबे, तुषार कांति बोस तथा ई.वी. मुरली को प्रदान किया जा चुका है।

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में ज़िलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए ज़िलों के गठन की घोषणा के साथ ही अन्य कई घोषणाएं की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा घोषित चार नये जिले हैं- मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़।
- उन्होंने राज्य में 18 नई तहसीलों के गठन का भी ऐलान किया।
  - इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अन्य घोषणाएँ भी की-
  - सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में महिलाओं के लिये 'मिनीमाता उद्यान' के निर्माण की घोषणा।
  - महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु-सीमा का बंधन समाप्त करने की घोषणा की।
  - 'मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना' अब 'श्री धन्वन्तरी योजना' के नाम से जानी जाएगी।
  - राज्य में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिये नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने की घोषणा
  - ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज ज़मीन का हक दिलाने के लिये 'स्वामित्व योजना' प्रारंभ करने की घोषणा।
  - 'डायल 112' सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किये जाने की घोषणा की।
  - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में काबिज लोगों को हक दिलाने के लिये राज्य में स्वामित्व योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा।

इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

- 14 अगस्त, 2021 को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम (IHCI) के तहत रायपुर ज़िले के सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 15,634 पंजीकृत रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिये सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह रैंकिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन के छत्तीसगढ़ प्रतिनिधियों द्वारा तिमाही रिपोर्ट पर आधारित थी।
- स्वास्थ्य केंद्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये रोगियों की संख्या, रक्तचाप की नियंत्रण दर, अनुवर्ती दवाओं की उपलब्धता और नए रोगी की खोज के आधार पर 100 अंकों पर रैंकिंग दी जाती है।
- रायपुर मार्च 2020 से IHCI लागू कर रहा है। इसके तहत रक्तचाप के रोगियों की जाँच की जाती है और दवाएँ तथा सलाह दी जाती है। अब तक 15,634 मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मंदिर हसौद (85 अंक) पहले स्थान पर रहा। आरंग ब्लॉक पीएचसी चंद्रखुरी ने 80, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा (78), शहरी पीएचसी चंगोराभाथा (77), पीएचसी तोरला (74), पीएचसी मंधार (73) और तिल्दा ब्लॉक पीएचसी बांगोली (65) ने स्कोर किया।

नोट :

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉ. मीरा बघेल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। डॉक्टरों, रेजिडेंट मेडिकल असिस्टेंट्स, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और रेजिडेंट हाउस ऑफिसर्स को भी सर्टिफिकेट दिये गए।

जगदलपुर में कैनोइंग-क्याकिंग की खेल सुविधा प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री और ज़िले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर में कैनोइंग-क्याकिंग खेल की सुविधा का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में इस नई खेल सुविधा से यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस खेल से देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिलेंगे।
- उद्योग मंत्री ने इस नई खेल सुविधा का लोकार्पण करते हुए कहा कि आदिवासी अंचल में अनेक खेल प्रतिभाएँ हैं, उन्हें खेल के इस नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लखमा ने कैनोइंग-क्याकिंग खेल के लिये प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं का उत्साहवर्द्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ भी दीं।
- उन्होंने ज़िला प्रशासन की पहल से उपलब्ध कराई गई खेल सुविधा का युवाओं से अधिक-से-अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया तथा दलपत सागर की सफाई अभियान की सराहना की।
- उन्होंने कहा कि दलपत सागर की इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिये किये गए प्रयास से इस अंचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, कैनोइंग-क्याकिंग खेल से दलपत सागर का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा।

गम्हरिया गाँव बना प्लास्टिक और कचरा मुक्त

चर्चा में क्यों ?

- 17 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के गम्हरिया गाँव को प्लास्टिक और कचरा मुक्त घोषित किया गया। इससे पहले इसे खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँव घोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- यह गम्हरिया में सूरजपुर स्वयं सहायता समूह की 'सफाई मित्र' महिलाओं के माध्यम से संभव हुआ है, जो घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं। ग्रामीण अब उन्हें सम्मानपूर्वक 'स्वच्छता दीदी' कहते हैं।
- समूह ने कचरा निपटान और कचरा प्रबंधन को कमाई का एक अतिरिक्त स्रोत बनाया है। पिछले एक साल में उन्होंने 63,000 रुपए कमाए।
- गम्हरिया के सरपंच विलियम कुजूर ने बताया कि गाँव में सेग्रीगेशन शेड (ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन केंद्र) बनाया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से धन उपलब्ध कराया गया।
- स्वयं सहायता समूह की सचिव सुनीता कुजूर ने बताया कि पॉलीथिन, खाद्य पदार्थों के पैकिंग रैपर, प्लास्टिक के सामान, लोहे के कबाड़ और काँच जैसे ठोस कचरे को अलग-अलग करके बेचा जाता है।
- उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 से 12 महिलाएँ समूह के लिये काम कर रही हैं। समूह प्रत्येक घर से 10 रुपए प्रतिमाह और कूड़ा उठाने के लिये दुकानदारों से 20 रुपए प्रतिमाह एकत्र करता है।

नोट :

'सुगंधित कोंडानार अभियान'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 'सुगंधित कोंडानार अभियान' के तहत आम के बागों (अमरई) को विकसित करने के हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ के कोंडागाँव ज़िले के राजागाँव में 1,000 अल्फांसो प्रजातियों का रोपण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कोंडागाँव विधायक मोहन मरकाम, ज़िला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार व अन्य प्रतिनिधियों ने राजागाँव में 25 एकड़ क्षेत्र में लेमनग्रास, पामारोसा, पचौली और अल्फांसो के 1000 पौधों का रोपण किया। इसके साथ ही अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा नीलगिरि और बांस के पौधे भी लगाए गए।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जून, 2021 को 'सुगंधित कोंडानार अभियान' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ज़िले को एरोमा हब बनाना तथा किसानों को अतिरिक्त कमाई के लिये सुगंधित फसल की खेती को बढ़ावा देना है।
- इस अभियान के तहत ज़िले के 2,000 एकड़ की वन, कृषि और निजी भूमियों पर सुगंधित फसलों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही ज़िले में 20 करोड़ की लागत से संयंत्र स्थापित कर सुगंधित पदार्थों का निर्माण किया जाएगा।

प्रमोद कुमार शुक्ला

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिये शिक्षकों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची घोषित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के करपावण्ड-बकावण्ड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के व्याख्याता प्रमोद कुमार शुक्ला का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष देश भर के 44 शिक्षकों का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयन हुआ है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। प्रमोद शुक्ला इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के एकमात्र शिक्षक हैं।
- प्रमोद शुक्ला का चयन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ईएमआरएस कोटा में हुआ है।
- इनके अलावा छत्तीसगढ़ से शिक्षा विभाग ने तीन शिक्षकों के नाम चयनित कर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये भेजे थे, लेकिन नेशनल ज्यूरी ने इनका चयन नहीं किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है।

ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये ओलंपियाड

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाई सिंह टेकाम ने राज्य भर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये ओलंपियाड का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह ओलंपियाड स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम के सरकारी स्कूलों के विज्ञान, गणित और अंग्रेज़ी में विद्यार्थियों की उपलब्धियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये आयोजित किया जा रहा है।

नोट :

- इस मूल्यांकन के चार स्तर हैं- प्राथमिक स्तर (कक्षा 3 से 5), माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8), हाई स्कूल स्तर (कक्षा 9, 10) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11, 12)।
- विज्ञान विषय के ओलंपियाड में 7 हज़ार 232 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें प्राथमिक स्तर के 1587, माध्यमिक स्तर के 2621, हाई स्कूल स्तर के 1861 और हायर सेकेंडरी स्तर के 1163 विद्यार्थी शामिल हुए।
- ओलंपियाड में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति के हैं। प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को स्कूल, ज़िला और राज्यस्तर पर रैंक दी जाएगी।
- आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गणित विषय का ओलंपियाड 25 अगस्त को और अंग्रेज़ी विषय का 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद स्मारक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

- 20 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में नवीनीकृत शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- पहले यह नगर निगम द्वारा संचालित हिंदी माध्यम का स्कूल था, जिसे अब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत लाया गया है।
- इस स्कूल का नवीनीकरण किया गया है और गुणात्मक रूप से व सौंदर्य की दृष्टि से इसे बदला गया है।
- स्कूल में अब एक आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और एक बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध है।

'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' की दूसरी किस्त का भुगतान

चर्चा में क्यों ?

- 20 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के तहत राज्य के 21 लाख किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1,522 करोड़ रुपए हस्तांतरण किये।

प्रमुख बिंदु

- राजीव गांधी की जयंती 'सद्भावना दिवस' पर आयोजित एक समारोह में बघेल ने राज्य के 21 लाख धान एवं गन्ना उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 1,522 करोड़ रुपए ई-ट्रांसफर किये।
- किसानों को जारी राशि में से धान उत्पादक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 22 करोड़ तीन लाख रुपए की राशि अंतरित की गई।
- इसके अलावा उन्होंने 'राजीव गांधी गोधन न्याय योजना' के तहत पशुपालकों एवं संग्राहकों से क्रय किये गए गोबर तथा गोठान समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को कुल 9.03 करोड़ रुपए राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया।

नव घोषित ज़िला मनेंद्रगढ़ का नाम अब 'मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर'

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि हाल ही में घोषित चार नए ज़िलों में से एक ज़िला मनेंद्रगढ़, अब 'मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर' के नाम से जाना जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री बघेल ने अपने सरकारी आवास पर दो नए घोषित ज़िलों- 'मनेंद्रगढ़' और 'शक्ति' के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि नए ज़िलों की घोषणा के पीछे प्रमुख विचार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और अन्य क्षेत्रों में तेज़ी से काम करना था।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से देश का नौवाँ सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ कई क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। भौगोलिक स्थिति के कारण सरकारी योजनाओं को आम जनता तक ले जाने में सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए ज़िलों के बनने से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी तथा शासन को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राज्य में ज़िलों का पुनर्गठन कर मनेंद्रगढ़ सहित चार नए ज़िलों के गठन की घोषणा की थी।

शत-प्रतिशत टीकाकरण वाला प्रदेश का पहला ज़िला बना रायगढ़

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2021 को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला ज़िला बन गया है, जहाँ सभी वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज मिली है।

प्रमुख बिंदु

- एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ज़िले में टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य 20 अगस्त को पूरा कर लिया गया था, जिसकी घोषणा 21 अगस्त को की गई।
- लक्ष्य के अनुसार ज़िले में कुल जनसंख्या 16 लाख 94 हज़ार 234 में से 10 लाख 42 हज़ार 625 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जानी थी, जिसे पूरा कर लिया गया है।
- यहाँ लक्ष्य के अनुसार 18 साल से अधिक आयु वर्ग के शत-प्रतिशत लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। लक्ष्य को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग व ज़िला प्रशासन को 217 दिन लगे।
- स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से रायगढ़ पूरे प्रदेश में अग्रणी रहा है। बीते 26 जून को ज़िले में महाटीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.43 लाख से अधिक वयस्कों को टीका लगाया गया था।

गणित ऑलम्पियाड

चर्चा में क्यों ?

- 25 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धियों का ऑनलाइन आंकलन करने हेतु गणित विषय के ऑलम्पियाड का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑलम्पियाड में 10 हज़ार 466 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें प्राथमिक स्तर के 2411, माध्यमिक स्तर के 3860, हाईस्कूल स्तर के 3045 और हायर सेकेंडरी स्तर के 1149 विद्यार्थी शामिल हुए।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 19 अगस्त को विज्ञान विषय के ऑलम्पियाड में 7 हज़ार 232 विद्यार्थी शामिल हुए थे।
- आंकलन को चार स्तर- प्राथमिक स्तर कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक, माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं तक, हाई स्कूल स्तर कक्षा 9वीं एवं 10वीं और हायर सेकेंडरी स्तर कक्षा 11 एवं 12वीं में विभाजित किया गया है।
- इसमें आंकलन कार्य पूर्ण होते ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर विद्यालय, ज़िला एवं राज्य स्तर पर विद्यार्थियों की रैंकिंग कर विद्यार्थियों का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में इन अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों के बच्चों की उपलब्धियों का आंकलन विज्ञान, गणित और अंग्रेज़ी विषय के ऑलम्पियाड के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य के 1242 गोठान हुए स्वावलंबी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य के कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना 'सुराजी गाँव योजना' के 'गरुवा' घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 5,963 गोठानों में से 1,242 गोठान स्वावलंबी हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ ज़िले में सर्वाधिक 189 गोठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरे नंबर पर कबीरधाम ज़िले में 141 गोठान तथा तीसरे क्रम पर राजनांदगाँव ज़िले में 101 गोठान स्वावलंबी हुए हैं।
- इसी प्रकार गरियाबंद ज़िले में 25, धमतरी में 43, बलौदाबाज़ार में 49, रायपुर ज़िले में 25, दुर्ग में 64, बालोद में 30, बेमेतरा में 22, कोरबा में 61, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 25, जांजगीर-चांपा में 44, बिलासपुर में 34, मुंगेली में 20, कोरिया में 23, जशपुर में 36, बलरामपुर में 18, सरगुजा में 39, सूरजपुर में 22, कांकेर में 69, कोंडागाँव में 21, दंतेवाड़ा में 29, नारायणपुर में 5, बस्तर में 26, बीजापुर में 12 तथा सुकमा ज़िले में 18 गोठान स्वावलंबी बन चुके हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,107 गाँवों में गोठान के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमं6 से 5,963 गोठानों का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ पर गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण सहित अन्य आयमूलक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं।
- वर्तमान में 3,220 गोठानों का तेज़ी से निर्माण कराया जा रहा है, शेष 924 गोठानों के निर्माण का कार्य अभी शुरू कराया जाना है।
- अब तक 4 हज़ार से अधिक गोठानों में लगभग 7,600 एकड़ में हरा चारा लगाया गया है, जिसमें हाईब्रिड नेपियर घास का रोपण एवं अन्य चारा बुआई की गई है।

वन अधिकार दावों को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे देश में अग्रणी राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में अब तक 4 लाख 86 हज़ार व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के अंतर्गत 21 लाख 95 हज़ार 228 हेक्टेयर रकबा की भूमि वितरित की गई है।
- इनमें व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत 4 लाख 41 हज़ार 502 हितग्राहियों को 3 लाख 60 हज़ार 619 हेक्टेयर रकबा और 44 हज़ार 524 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत 18 लाख 34 हज़ार 609 हेक्टेयर रकबा की वितरित भूमि शामिल है।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के लोगों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्हें अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने जनजातीय वर्ग के समग्र उत्थान और उनकी उद्यमिता दक्षता के विकास पर विशेष ज़ोर दिया।
- साथ ही, उन्होंने प्रदेश के वनांचल तथा आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के स्वास्थ्य सुधार और बेहतर जीवनयापन की दिशा में संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के भी निर्देश दिये। इसी तरह जनजातीय वर्ग के समग्र विकास हेतु उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें अधिक-से-अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया।

नोट :

ट्राईफेड के आउटलेट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट में ट्राईफेड के आउटलेट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस आउटलेट में बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित बेलमेटल कलाकृति, कपड़े, वन उत्पाद को प्रदर्शनी सह-विक्रय के लिये रखा गया है।
- एयरपोर्ट में खुले इस आउटलेट से आने वाले आगंतुकों को बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पाद एक स्थल पर मिल सकेंगे। साथ ही, बस्तर की कला का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार होगा। इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ यहाँ के कलाकारों को मिलेगा।

वनधन विकास केंद्रों को मिला सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में सेमरा स्थित फूड पार्क में आयोजित ट्राईफेड के वनधन सम्मेलन, 2021 कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न वनधन विकास केंद्रों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के बस्तर ज़िले से वनधन केंद्र कुरूंदी, बकावण्ड, घोटिया और धुरागाँव को अवॉर्ड प्रदान किया गया।
- इसके अलावा राज्य के वनधन केंद्र कडेना धरमजयगढ़ (रायगढ़), वनधन केंद्र गरियाबंद, वनधन केंद्र डोंगानाला कटघोरा (कोरबा), वनधन केंद्र बरोडा (बलौदा बाज़ार), वनधन केंद्र कौरिनभाटा (राजनांदगाँव), वनधन केंद्र दुगली (धमतरी), वनधन केंद्र नारायणपुर, वनधन केंद्र पनचक्की (जशपुर) को भी विभिन्न वर्गों में अवॉर्ड दिये गए।
- इन वनधन विकास केंद्रों को 5 वर्ग में संचालन के पैमाना, उत्पाद की अधिकतम बिक्री, मूल्यवर्द्धित वस्तुओं की श्रेणी, एमएफपी योजना के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं मार्केटिंग के लिये नवाचार और रचनात्मक विचार के आधार पर सम्मानित किया गया।
- केंद्रीय मंत्री ने सेमरा ट्राईफेड में लगाए गए स्टाल में बस्तरिया उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने वनधन विकास समिति से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा इमली, काजू, तैलीय बीज, मूसली और महुआ के प्रसंस्करण के साथ ही गढ़ कलेवा के स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा स्थापित शबरी के हस्तशिल्प, बस्तर कलागुड़ी कलाकृतियाँ, रेशम उत्पादन, हरिहर बस्तर के उत्पाद, ट्राईब्स इंडिया के उत्पाद, बस्तर पपीता, बस्तर कॉफी, बाँस कला केंद्र और हथकरघा से तैयार उत्पादों का निरीक्षण किया।

सूखा प्रभावित किसानों को वित्तीय मदद

चर्चा में क्यों ?

- 29 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों (चाहे उत्पादन प्रभावित हो या नहीं) को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने वर्तमान खरीफ मौसम में धान, कोदो-कुटकी, अरहर की बुवाई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है (चाहे उत्पादन हो अथवा न हो) तो उन्हें सरकार वित्तीय सहायता देगी।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मान से मदद दी जाएगी।
- राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने खरीफ फसलों मुख्यरूप से धान, बाजरा और दलहन को प्रभावित किया है।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 'पंडवानी' कलाकार स्वर्गीय पुनाराम निषाद और 'नाचा-गम्मत' कलाकार स्वर्गीय मदन कुमार निषाद की जीवनी के प्रकाशन की भी घोषणा की।

नोट :